THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Sir, I have absolutely no hesitation in making my statement now. The only point is that it is listed lor five o'clock in the afternoon. It is entirely up to you to decide. I am in your hands.

THE VICE-CHAIRMAN- (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): What is the pleasure of the House? Do you want that the statement be made at this stage or at the time at which it is listed?

′ SHRI JAGESH DESAI: Here we can find a solution. If the Members are here, those Members whose names are given, we can take it up now. But if the Members are not here, then...

SHRT S. B. CHAVAN (Maharashtra): *J* would like to point out that once you notified that the statement is going to be made at a particular time, it might 'be that Members will come at that time, those who are interested in making points on the statement that the honourable Minister 5s going to make. So if we try to advance the same, it will be doing injustice to the Members who are interested in the discussion of the statement. That is why I request you that instead of making the statement immdiately, it should be made only at five o'clock.

SHRI YASHWANT SINHA: I aim entirely in the hands of the House.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I think some of the Members who have given their names are not at the moment here. Whether they return or not is a matter of probability, but they cannot be denied the privilege.

SHRI JAGESH DESAI: Even if the stafwnent is made before five o'clock, Itey have a right—I agree.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): Is there any Special Mention? We can go back to Special Mentions, if you like.

डा० रत्नाकर पाण्डेय : मान्यवर, प्रतिदिन और भी बिजनेस लिस्टेड होना चाहिए, ताकि यह दयनीय और हास्यापद स्थिति इस महान सदन की न हो।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): We will take up the Special Mentions. We will resume that. Yes, Mr. Santosh Bagrodia.

SPECIAL (MENTIONS—Contd!.)'..

C OMMUNAL TROUBLE AND TER-RORIST VIOLENCE IN RAJASTHAN

SHRI SANTOSH BAGRODIA (RAJASTHAN): Mr. Vice-Chairman, Sir, I would like to draw the attention of the Government to the fact that the Union Home Ministry had sent a message, sometime last month, to the State Intelligence agencies that they should be on maximum alert to meet the threat of communal trouble and terrorist violence in Rajasthan.

Sir Rajasthan is one State which was absolutely free from communal trouble and also from terrorism, which were unknown in our State. People of all communities—Hindus, Muslims, Sikhs, ^Christians, (etc;.,—were Jiving like brothers, "without any ilL-feeling whatsoever. When the present communal Government, though in minority, came to power in the State, the entire communal fabric of the State has been shredded into pieces.

जो यह रंग-बिरंगा कपड़ा हमारे पूर्वजों ने बहुत कुर्बानी और बलिदान से बनाया, उसे ही आज के कुछ कम्युनिलिस्ट लीडर्ज ने गरीब जनता को भुलावे में देकर कुर्सी पकड़ ली और पहला काम किया कि इस सुंदर रंग-बिरंगे कपड़े को चारों तरफ से फाड़ डाला।

इस कपड़े को फिर से बनाने के लिए बहुत बड़ी कुर्बानी देनी पड़ेगी । उसकी ताकत और इच्छा केवल कांग्रेस पार्टी में है और उसके नेता राजीव गांधी में है।

It appears that the present communal troubles in different parts of the State have been started in collusion with the Government and the same have been further aggravated j by the Pakistani intruders. Though the local police do not confirm this, they do not rule out the possibility either.

Sir, what happened in Jaipur and Jodhpur? Entire localities were destroyed and the administration was a silent, stand-by watcher when ordinary helpless citizens were being killed, women were being raped and property was being destroyed. I demand with the highest tradition (of political morality that the present Chief Minister of Rjylasthan should resign as it has been done by two Congress Chief Ministers of Karnataka and. Andhra Pradesh as and when the communal troubles took place in those States.

I further add that in March this year a gang of bomb-manufacturers j was busted in Jaipur. *1%* was then established that Pakistani intruders were running this camp and that they were training the local people in Jaipur and Kota were huge stocks of crude bombs were also seized.

The Ganganagar sector is being used as a conduit by Punjab terrorists for smuggling arms in Rajasthan. With the installation of the new Gov-, ernment in Pakistan, the extremists have recived further encouragement m Ganganagar and Bikaner in view _. of the utterances of the new Pakistan Prime Minister. This is further strengthened with the BSF's encounter with a group of extremists on the IrtdcPakistan border |n the Ganganagar district, and such encounters have become a daily happening.

I want the Union Government to assure the people of Rajasthan in particular and the entire country in general that the Indo-Pakistan borders in Rajasthan will be fully sealed and that no Pakistani intruder will be allowed to enter the State of Rajasthan. The Union Government should also give a very strict warning to the State Government that it must be very vigilant and that all possible measures should be taken to avoid communal trouble. Or else the State Government should be dismissed, and the State should be put under President's rule to save the life and property of the ordinary people of Rajasthan.

Mr. Chairman, Sir, recently I visited Jaipur and also other parts of the State. Because of the communal trouble it was just impossible to move, we were just not able to move from one district to another. I therefore, request the Central Government to take a serious note of it.

With these words, I thank you very much, Mr. Vice-Chairman, Sir.

THE VICE-CHAIRMAN (PROP. CHANDRESH P. THAKUR); Yes, Dr. Abrar Ahmed. डा. अबरार अहमद खान । आप थोड़ा सा संक्षेप में बोलिएगा ।

डा. अबरार अहमद (राजस्थान) : मैं संक्षेप में ही बोलूंगा । वैसे आज में समझता हूं कि ...

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : वह समझने की जरूरत नहीं है, आपको जो बोलना है बोलिए, एडीटोरियल करने की जरूरत नहीं है । आप बोलिए ।

डा० अबरार अहमद : मैं राजस्थान के बारे में, अभी जो बागड़ोदिया जी बोल रहे थे उसी संबंध में जो सांप्रदायिक झगड़े हुए आपके माध्यम से सरकार तक पहुचाना चाहता हूं ।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : सांप्रदायिक झगड़े कहां नहीं हुए ?

डा. अबरार अहमद : महोदय, सांप्रदायिक झगड़े तो देश में बहुत जगह हुए हैं लेकिन राजस्थान में जो सांप्रदायिक झगड़े उनकी स्थिति थोड़ी उन झगड़ों से अलग है। राजस्थान के अन्दर, 23 अक्तूबर को जब भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री आडवाणी जी को गिरफ्तार किया गया उस समय जिस प्रकार की सभायें करके उत्तेजित भाषण दिए गए, उपसभाध्यक्ष महोदय, भाषण देना तो कोई बात नहीं लेकिन सरकार के मंत्री भाषण दें, राज्य सरकार के मंत्री भाषण दें और वह लोगों को उत्तेजित करें वह इस बात का आग्रह करें कि किसी भी तरह से बंद सफल होना चाहिए चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े और जयपुर जोधपुर में उसी के कारण से वह गुलाबी नगरी जो लाल रंग में रंग दी गई, जो खून के अन्दर रंग दी गई जिसके अन्दर सरकार के मुख्य मंत्री का सरकार के मंत्रियों का बी.जे.पी. की सरकार का खुल्लम-खुला हाथ था। महोदय, वहां जिस प्रकार से गोलियों से लोगों को मारा गया, जिस प्रकार से गोलियां चलाई गईं, गोलियां चलाई जाती हैं मोब पर, गोलियां चलाई जाती हैं दुकानों के ताले तोड़ने वालों पर, दुकानें लूटने वालों पर, लेकिन जितनी लाशें मिलीं एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि किसी दुकान का ताला तोड़ने वाले आदमी पर गोली चलाई हो, सी दुकान के बाहर लूट करने वाले आदमी पर गोली चलाई हो, जो गोलियां चलीं वह निर्दोष लोगों पर चलीं। जिस प्रकार से पुलिस का व्यवहार रहा, जिस प्रकार से वहां की सरकार के मंत्रियों का उसके अन्दर हाथ रहा वहां की लूट-पाट में, वहां की आगजनी में वह मंत्री, वहां की राज्य सरकार के मंत्री ने जिस प्रकार से खुला नृत्य, नंगा तांडव किया उसकी जितनी निंदा की जाए वह बहुत कम है।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी ठाकुर) : जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उन पर इतना बड़ा प्रहार न कीजिए, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

डा० अबरार अहमद : महोदय, प्रहार नहीं, यह तो वास्तविकता है। सारी प्रेस इस बात को जानती है सारे अखबारों में प्रेस के जरिए यह आया कि 80 से अधिक लोग मर गए वहां आज कौन सी इन्क्वायरी चल रही है ? मात्र सी.आई.डी. की इन्क्वायरी है।

महोदय पुलिस और सी.आई.डी. के अंदर किसी प्रकार का अंतर नहीं होता है वहां मात्र सी.आई.डी. की इंक्वायरी की बात है। किसी प्रकार की जुडीशियल इंक्वायरी की बात नहीं कही गई है। भारतीय जनता पार्टी के नेता सारे देश में मांग करते हैं जुडीशियल इंक्वायरी की, लेकिन जिस प्रदेश में उनकी सरकार है वहां क्यों नहीं जुडीशियल इंक्वायरी की गई। क्यों नहीं किसी हाईकोर्ट के न्यायधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश से जुडीशियल इंक्वायरी की गयी ? उन मांग के लिए मैं दो दिन धरने पर बैठा, उपवास रखा, वहां बहुत से लोगों ने मांग की लेकिन वहां की सरकार कानों में रूई दिए बैठी है क्योंकि अगर कोई जुडीशियल इंक्वायरी होती है, सुप्रीम कोर्ट का जज उसकी जांच करता है तो निश्चित रूप से उस सरकार के मुख्य मंत्री और दूसरे मंत्रियों के मुंह पर से पर्दा उठेगा। उन पुलिस अधिकारियों के मुंह से पर्दा उठगा जिन्होंने उनसे मिलकर लोगों को गोलियों से मारा है, लोगों को घर से बेघर किया है।

अगर वहां की सरकार चाहती तो किसी भी कीमत पर वहां झगड़ा नहीं होता।

उपसभाध्यक्ष (प्रो चन्द्रेश पी ठाकुर) : आप एसोसिएट कर रहे हैं उस स्पेशल मेंशन से ?

डा० अबरार अहमद : मैं एसोसिएट नहीं कर रहा हूं। मैं उसमें बहुत-सी बातें जोड़ना चाहता हूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : वह आप नहीं कर सकते

डा. अबरार अहमद : मैं आपके माध्यम से प्रधान मंत्री तक यह बात पहुंचाना चाहता हूं कि वहां कर्फ्यू के वक्त प्रधान मंत्री चन्द्रशेखर जी भी जयपुर गए थे, लेकिन वे मात्र भैरोंसिंह शेखावत की माताजी के देहावसान के मौके पर भेंट कर आगए। सारे जयपुर में कर्फ्यू लगा हुआ था। वहां जो 80 लाशें निकली थीं। उनके घर वाले टकटकी लगाए देख रहे थे कि प्रधान मंत्री जी जयपुर आए है तो हो सकता है कि हमारी वेदना सुनने के लिए आए हो सकता है हम से मिलने आएं हो सकता है हम रे उजड़े हुए घरों को देखने आएं। हम री बर्बाद पुरातन नगरी जो लहू से लाल हो गयी है उसे देखने के लिए आएं, लेकिन वे नहीं आए। महोदय मैं आपके माध्यम से यह बात उन तक पहुंचाना चाहता हूं कि वे जयपुर जाएं, । जब हम उनसे मिले थे तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया था कि मेरा जयपुर जाने का प्रोग्राम है और जैसीकि मुझे जानकारी है, वह 29 तारीख को फिर राजस्थान जा रहे हैं। तो अगर उनमें जरा भी उन मारे गए लोगों के परिवारों के प्रति वेदना है तो जयपुर में जहां लोग जल गए हैं, मर गए हैं उनको जाकर देखें।

महोदय, मैं एक बात बहुत स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि चन्द्रशेखर जी और भैरोंसिंह शेखावत जी का चाहे किसी प्रकार का दोस्ताना हो याराना हो या किसी प्रकार के वायदे हों, लेकिन राजस्थान में जो सांप्रदायिक झगड़े हुए हैं उसके बीच में वह दोस्ती को न लाएं। वहां वे सिर्फ प्रधान मंत्री के रूप में जाएं। वहां दंगा पीड़ितों की आंखों से न बचें। उनकी आहें सुनें उनकी बातें सुनें और जो भी वह कहें कि किस तरह से राजस्थान की सरकार ने उन पर जुल्म किया है' कैसे वहां के मंत्री लूटपाट में मौजूद थे, कैसे उस परिस्थिति में उनके मंत्री शामिल थे– वह सब सुनें।

उपसभाध्यक्ष (प्रो चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप बैठ जाइए। भावावेश में मत आइए।

डा. अबरार अहमद : मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हू 24 और 25 अक्तूबर, को जोधपुर, ब्यावर और जयपुर में जो कुछ हुआ, वह विश्वास नहीं होता। वह जयपुर जिसको गुलाबी नगरी कहा जाता था और जिस जयपुर की मिसालें दी जाती थीं कि 250 साल में जयपुर में कभी सांप्रदायिक झगड़ा नहीं हुआ, 1947 में भी वह जयपुर बचा रहा, लेकिन आज जयपुर के बारे में सोचना पड़ता है। मैं आपकी जानकारी में एक बात लाना चाहता हूं कि आज पढ़े-लिखे लोग भी पलायन कर रहे हैं। यह शायद केन्द्र की जानकारी में नहीं होगी क्योंकि वहां की सरकार उस पर पर्दा डालना चाहती होगी। आज वहां पढ़ा-लिखा आदमी भी सोचता है कि मैं कौन-सी बस्ती में रहूं या न रहूं।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : अब आप बैठ जाइये।

डा. अबरार अहमद : मैं दो-तीन बातें आपके माध्यम से कहना चाहता हूं। इन परिस्थितियों को देखते हुए प्रधान मंत्री जी वहां जायें, उनके दुःख-दर्द को सुनें, उन पीड़ितों को सुनें और जो भी समुचित कार्यवाही राज्य सरकार के खिलाफ हो, वह होनी चाहिए। महोदय, यह बड़ी दुखदायी स्थिति है कि न वहां प्रधान मंत्री जी गए, न गृह राज्य मंत्री जी गए। इसलिए मैं मांग करता हूं कि कम-से-कम सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश द्वारा वहां की जुडीशियल इंक्वायरी हो क्योंकि वहां बी.जे.पी. की सरकार है, आडवाणी जी की गिरफ्तारी के बाद ये झगड़े हुए। वहां के मंत्री खुद उसमें सम्मिलित थे। उनका मशीनरी से अग्रह था कि किसी भी प्रकार से बंद सफल होना चाहिए चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। "कुछ भी करना पड़े" ये जो शब्द थे, उसी का नतीजा था कि वहां गोलियां चलीं और खून-खराबा हुआ।

[डा० अबरार अहमद]

महोदय, मैंने आपसे शुरू में निवेदन किया कि गोलियां माब पर चलायी जाती हैं, दुकानें लूटने वालों पर, ताला तोड़ने वालों पर चलायी जाती हैं। लेकिन वहां जितनी लाशें मिलीं, उनके बारे में वह सरकार या पुलिस कह दे कि उनमें से एक भी किसी दुकान का ताला तोड़ने वालों की थी, किसी माब पर गोली चली, उनमें से थी या किसी का माल लूटकर ले जानेवाले की थी। वह लाशें निर्दोष लोगों की थीं और उसके अंदर पूरा षडयंत्र था, पूरी साजिश थी। तो वहां पर उसकी जूडिशियल इंक्वायरी हो। जो वहां लोगों पर गुजरी है, उसे वे बताने के लिए तैयार हैं। मैं तीन बार उन लोगों के बीच में गया हूं। जूडीशियल इंक्वायरी में जब न्यायधीश वहां जाएगा तो उसको वे बतायेंगे कि किसने उन्हें मारा और किसने घर से बेघर किया।

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप ने अपनी बात कहदी ?

डा० अबरार अहमद : महोदय, एक घर के अंदर 7 आदमियों को जिंदा जलाया गया . . .

जिसमें एक स्त्री के पास एक छोटा सा बच्चा था और उस स्त्री के जलने के बाद उस बच्चे को डाक्टर उसके शरीर से अलग नहीं कर सके। सात आदमी एक ही कमरे में, जो मुश्किल से 3 फीट 8 फीट का होगा, उसमें जिंदा जलाए गए, लोगों को कत्ल किया गया। ऐसे-ऐसे हादसे वहां हुए हैं, लेकिन इन्क्वायरी, मात्र सी.आई.डी. इंक्वायरी हो रही है, जबकि जुडिशियल इन्क्वायरी होनी चाहिए। वहां बी.जे.पी. को बर्खास्त होना चाहिए। इसके साथ ही साथ प्रधान मंत्री जी खुद वहां जाएं और वहां की स्थिति को देखें। धन्यवाद।

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA (Jammu and Kashmir): Mr. Vice-Chairman, I associate myself with the sentiments expressed by Mr. Abrar Ahmed in this special mention. I would further request that the political party which indulges in com-munaller shouldbe banned

श्री रफीक आलम (बिहार) : सर, यह बड़ा गंभीर मामला है। . . .

उपसभाध्यक्ष (प्रो० चन्द्रेश पी० ठाकुर) : आप भी एसोसिएट करना चाहते हैं ?

श्री रफीक आलम : जी, मैं एसोसिएट कर रहा हूं, इसमें जुडिशियल इंक्वायरी होनी चाहिए और सिर्फ राजस्थान में ही नहीं, जहां-जहां भी कम्युनल राइट्स हुए हैं, वहां होनी चाहिए। इसमें जो भी दोषी हों, चाहे हमारे नेता हों, चाहे एम.एल.एज. हों, चाहे एम.पीज हों, जो भी हों, उनके खिलाफ गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए।

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR): I think that there are no two opinions that the country is going through a very unfortunate stage. The communal tensions and riots that are taking place an different parts of the country are reprehensible. It is further reprehensible that it has a new pattern If there are vested interests taking a sort of part in it in a calculated way, I am sure the Government will take a note of that and move with dispatol. I would like to draw the attention of the Leader of the House towards the sentiments expressed by Members that the communal tension is creating a lot of problems. There are certain news patterns and perhaps the Government would like to apply its mind to that. If he wishes to respond at this stage, he is most welcome.

SHRI SHABBIR AHMAD SALARIA: A fullfledged discussion on this subject should be allowed.

THE LEADER OF THE HOUSE (SHRI YASHWANT SINGH): I would not like to respond in any detail at this stage. The only point I Would like to make is that the Government is very, very concerned with the kind of situation which has developed and it bag done all that it can t« see

that it is brought to an end immediately. I also believe that when we have a discussion later this afternoon regarding the business of this House, the Government on its part will have absolutely no objection to a full-scale discussion as some of the Members have been demanding in this House on the communal situation.

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR); So on that note let us adjourn till 5 o'clock when the Minister for Finance will make bis statement.

The House then adjourned at thirtytwo minutes past three of the clock till five of the clock.

5.00 P.M.

The House reassembled at five of the clock,

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH) in the Chair.

डा. रत्नाकर पाण्डेय (उत्तर प्रदेश): उपसभाध्यक्ष जी, आपको परे सदन की ओर से जन्मदिन की बधाई। आप 101 वर्ष तक जियें—स्वस्थ, कर्मठ।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Thank you. Now I request Shri Yashwant Sinha to make his statement on the current fiscal situation.

डा. रत्नाकर पाण्डेय: माननीय उप-सभाध्यक्ष जी, इसके पहले कि मंत्री महोदय जी स्टेटमेंट दें, मैं कहना चाहूंगा कि आज बड़ी दुखद स्थिति इस सदन में देखने को मिली है। 03.00 बजे के बाद इस माननीय सदन के पास कोई बिजनेस नहीं था कि हाऊस चल सके। करीब चार-सवा चार साल से मैं इस सदन का सदस्य हूं, एडजारन होता रहा है हाऊस मतभेदों को लेकर, लेकिन बिजनेस न हो और इसके लिये हाऊस एडजारन करना पड़े, यह भारतीय जनतंत्र के नाम पर एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। इस सरकार को मैं आगाह करना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने आपको समर्थन दिया है, अगर बिजनेस आप ठीक से चलाने में असमर्थ हों तो हमारे नेताओं से, यहां बैठे हैं हमारे डिप्टी नेता चव्हाण साहब और दूसरे लोग बैठे हैं, उनसे राय करके इस तरह से सदन को चलाइए ताकि भारत की जनता इस सर्वोच्च सदन के प्रति जो आस्था, मर्यादा और विश्वास रखती है, उसमें कमी न होने पाये।

मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि आप सरकार को निर्देश दें कि भविष्य में ऐसी गलती न हो।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह) मंत्री महोदय स्टेटमेंट ... (व्यवधान) ...

श्री रामेश्वर ठाकुर (बिहार): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं स्पष्टीकरण करना चाहूंगा। क्योंकि रिजर्व बैंक आफ इंडिया का बिल आने वाला था, यह हमें बताया गया था और उसमें मेरा नाम बोलने वालों में था और हमारे एक माननीय सदस्य कुलकर्णी जी का भी नाम था और हम लोग उस विषय पर बोलने वाले थे। प्रातः जिस समय सभा की कार्यवाही समाप्त हुई थी, हमें यह बताया गया था कि यह बिल साढ़े तीन बजे के बाद आने वाला है क्योंकि बहुत से सदस्य स्पेशल मेंशन में बोलने वाले थे। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे बी.जे. पी., जनता दल और कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, सब खाली करके चले गये बीच में ही और नतीजा यह हुआ कि हमने नाम दिया हुआ था बोलने वालों में, वह बोला नहीं। फलस्वरूप यह घटना हुई, नहीं तो हम सभी तो अपने वक्त से आ गये थे और हम मंत्री महोदय से भी मिले, सदन के नेता से, लेकिन उस समय तक चूंकि वे चले गये, इससे इस तरह की स्थिति पैदा हो गई नहीं तो मैं समझता हूं कि इस सरकार का या हमारे मंत्री महोदय का कोई दोष नहीं है, दोषी तो हम हैं जो हम समय पर नहीं आये।

डा. रत्नाकर पाण्डेय : केवल दो ही बिजनेस लिस्टिड थे माननीय उपसभाध्यक्ष जी । सरकार चलती रही पहले भी, दर्जनों बिजनेस लिस्टिड रहते थे ताकि एक न हो तो दूसरा हो । जो कमी है उसे सदन को स्पष्ट स्वीकार करनी चाहिये ।

वाणिज्य मंत्री, साथ में वित्त और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार (श्री सुब्रह्मण्यम स्वामी): कोई भी सरकार आये पांडेय जी नहीं छोड़ने वाले हैं ।

SHRI A. G. KULKARNI (Maha rashtra : Mr. Vice-Chairman, at the outset, I ana very happy today that my colleague, Dr. Ratnakar Pandey, raised an issue which is very impor tant and he is now seized of the matter that the House must run properly. I am very happy for that.

Secondly, Sir, I am- happy that today we are discussing it but as Mr. Rameshwar Thakur has rightly pointed out, I was also told that we should come back at 3.30 p.m. and that the Representation of the People (Amendment) Bill, 1990- will be taken up. But you know Dr. Swamy must have managed that this Bill is sent to the Select Committee because he is, what you call, a great manoeuvrer. He did his own tricks and he could do something more. It is very fine_ So, Sir, I have lost the chance. Now there is no chance to discuss the Reserve Bank of India (Arrsendment) Bill, 1990 again. But, Sir, the Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1990 ought to have been discussed. I would I request the Finance Minister and the Leader of the House to take it up because this is a very important subject for discussion because the Reserve Bank affects the priority sector for small scale industry, agriculture and total industry. But, Sir, I think, under the present rule there is no provision.

SHRI RAMESHWAR THAKUR: Sir, one request I would like to make. Since a statement on the present economic situation is going to be laid and we will be allowed to speak and I have given a notice already, I think, our colleagues also, if the Leader of the Opposition agrees. *(Interruptions)*

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): No, no. Please take your seat. Now I am telling you one thing. *(Interruptions).*

SHRI A. G. KULKARNI: It should be totally discussed.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SHANKAR DAYAL SINGH): Kulkarni Ji, may 1 tell vou one thing?

ठाकुर जी, नहीं-नहीं मैं समझ गया । तीनों माननीय सदस्यों ने . . . (व्यवधान) ठहर जाइये एक सैकेंड । मेरी बात को आप सुन लीजिये, बैठ जाइये । तीनों माननीय सदस्यों ने जो चिंता व्यक्त की है मंत्री महोदय स्टेटमेंट देने जा रहे हैं, दूसरे भी मंत्रीगण हैं इस संबंध में भी वे आपको आश्वासन देंगे जो चिंता आपने व्यक्त की है । कुलकर्णी जी और ठाकुर जी ने जो प्रश्न यहां उठाया है उसके बारे में अभी बिजनेस एडवाजइरी कमेटी में बहुत कुछ जो बातें हुई हैं उसका विवरण भी आपके सामने आने वाला है और जो आप डिक्कशन चाहते हैं उसकी गुंजाइश शायद उसमें की गयी है । यदि नहीं की गयी होगी तब उस पर भी विचार किया जायेगा ।

PROF. CHANDRESH P. THAKUR (Bihar): Sir, I have to make one simple submission. The issues are two. One is the procedural part, how much time was devoted, who was present and who could not be present. The other issue is, this was an occasion to discuss the working of the Reserve Bank of India and as a consequence, the working of the financial institutions under its supervision, so, from that point of view, the consideration before this House is, will this Government provide another occasion to discuss specifically the working of the Reserve Bank of India and the institutions under its supervision? I remember the Finance Minister made a mention that there are many occasions when financial issues are going to be discussed and we can bring the Reserve Bank of

India. That is his generosity. But the way the banking institutions are working and the kind of situation that we are beginning to face with regard to the sickness or the *f* impending sickness of the financial institutions at the apex or the lower level, the issue requires a systematic discussion. So 1 will submit through you, to the Government, let the Finance Minister provide some time for the discussion of financial institutions in general and the Reserve Bank of India and its effectiveness in run-■ ning the financial institutions efficiently in particular.

THE FINANCE MINISTER (SHRI • YASHWANT SINHA): I am prepared to respond to it.

डा. अबरार अहमद : उपसभाध्यक्ष जी, इस समय देश के अन्दर कितनी ज्वलंत समस्यायें हैं और आज यह सदन बिजनेस न होने की वजह से एडजोर्न किया गया। आज देश का प्रत्येक आदमी उन चिंताओं को सोचने के लिये मजबूर है। लेकिन इतना गलत मैसेज राष्ट्र के अन्दर चला गया कि इस राष्ट्र का सर्वोच्च हाउस बिजनेस न होने के कारण, किसी वत पर चिंतन के लिये कोई विषय न होने के कारण एडजोर्न किया गया । महोदय, किसी बिजनेस का लिस्टेड होना या लिस्टेड न होना महत्वपूर्ण नहीं है। इस सदन में अनलिस्टेड बिजनेस तीन-तीन दिन तक डिस्कस हुये हैं। अगर लिस्टेड बिजनेस नहीं था तो अनलिस्टेड बिजनेस लिया जा सकता था। आज देश के सामने इतनी ज्वलंत समस्यायें हैं जिनके लिये सदन का प्रत्येक मेंबर चिंतित है और चिल्ला-चिल्लाकर कहता है कि उन पर विचार होना चाहिये। तो कोई भी ऐसा विषय यहां पर प्रारंभ हो सकता था क्योंकि आज जो देश के हालात हैं वे किसी भी सदस्य से छिपे हुये नहीं हैं या किसी भी नागरिक से छिपे हुये नहीं हैं। तो यह जो गलत मैसेज चला गया, यह सदन की गरिमा के खिलाफ है।

मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि और जैसा कि रत्नाकर जी ने भी कहा कि भविष्य में इस प्रकार का मैसेज राष्ट्र को न जा पाये कि इस राष्ट्र के सर्वोच्च सदन के पास विचार के लिये कोई विषय नहीं है जिसके कारण आज डेढ़ घंटे तक सदन को एडजोर्न किया गया।

उपसभाध्यक्ष (श्री शंकर दयाल सिंह): I Now the Finance Minister to make his statement.

SHRI YASHWANT SINHA: Sir, before I read my statement, I would like to respond briefly, very briefly, because I have said something earlier today. But in view of the points which have been made, I think it is necessary for me to put the record straight. We hr.d two bills listed in the business for consideration before this House today.

Now, one of them came up, rather suddenly, at around 2.30 in the afternoon when the House reassembled. As the hon. Member, Shri Thakur, pointed out, this came up because some of our colleagues decided to absent themselves and **their** Special Mentions could not come and **take** the required amount of time. Now, if Mr. Thakur and Mr. Kulkarni were informed by somebody that this Bill was likely to come up by 3.30 P.M. it must have been on the basis of the fact that the Special Mentions would go on until 3.30 P.M. 1 know this because my colleague, Mr. Digvijay Singh, who was supposed **to pilot** this Bill, was also told that this **Bill would** come up around 3.30 P.M. **and that he** should be present here around **3.30** P.M. But fortunately he was present here **and** suddenly this Bill came when Mr. Thakur was presiding over the House. At that time we had no choice but, according to the business of the House, td take it **up.** It is very unfortunate that there was **a** misunderstanding as a result of which some hon. Members who had prepared to participate in this discussion fruitfully meaningfully and in an effective manner, as I know it personally, were denied this opportunity. When this matter was raised at the time when the Bill was passed, I **had got** up and responded. I say that we are **also** interested in taking the guidance of this House in this matter as **in other matters.**

[Shri Yashwant Sinha] and we will not like to deny ourselves this opportunity and, therefore, I have suggested that there will be enough opportunities in the course of the remainder of this Session to discuss some of the important issues which are bothering the Members on this particular subject. Now we have another Reserve Bank of India (Amendment) Bill, 1990 which is coming up. That Bill plus the Suppltmentary and the Appropriation Bill and even this also will give you an opportunity to make your point and, therefore, it is not our intention at all to deny the right to speak to anyone. The only point I would like to make is that while I share the concern of the hon. Member, Shri Ratnakar Pandeyji, that the business of the House must go on smoothly, I must put this on record that it was not because of any lock of desire or will or effort on our part that this happened. We certainly will be careful. The is a matter which we discussed ourselves in the Chamber just now and, I am sure, this occasion will not arise. This occasion arose because the Business Advisory Committee did not meet and lay down the business for the House.

Now, Sir, with your permission and after having said this, I would like to share the statement that I have, with the House.

STATEMENT BY MINISTER—THE CURRENT FISCAL SITUATION

[The Vice-Chairman (Prof Chandresh. P. Thakur) in the Chair]

THE VICE-CHAIRMAN (PROF. CHANDRESH P. THAKUR); All right, you may go ahead with the statement.

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): Mr. Vice-Chairman, Sir, I rise to make this statement before the House on some strategic issues in the management of the economy. It is a difficult conjuncture. The large fiscal imbalances persist. The balance of payments situation is serious. The inflationary presssures on the price level are considerable. It is essential for me to put the facts in perspective and share our thinking on these problems with honourable members.

The performance of the economy during the second half of 1980s was impressive in terms of growth rates, but this was associated with emergence of macro-economic imbalances. In recent years, we have witnessed a widening gap between the income and the expenditure of the Government which has led to mounting budget deficits. At the same time, there has been a steady increase in the difference between the income and the ex- ' penditure of the economy as a whole, which has led to persistent current account deficits in the balance of payments.

During the Seventh Plan period the budget deficit of the Central Government, which is only a partial measure of fiscal imbalance, fluctuated around a level of 2 per cent of GDp. The revenue deficit of Central Government rose from 2.2 percent of GDP in 1&85-86 to 2.8 per cent of GDP in 1989-90. However, the fiscal deficit of the Central Government, v/hich measures the difference between revenue and total expenditure, was more than 8 per cent of GDP throughout the Seventh Plan period, as compared with 6-1 per cent in 1980-81 and 3.2 per cent in 1974-75. This fiscal deficit had to be met by borrowing. The burden of serving this debt has now become onerous. Interest payments alone constitute 20 per cent of the total expenditure of the Central Government and 4 per cent of GDP, compared with 10 per cent and 2 per cent respectively in 1980-81.

The balance of payments situation has also been under considerable strain in recent years. During the Sventh Plan period, the current account deficit was 2.2 per cent of GDP as compared with 1.3 per cent of GDP during the Sixth Plan period. The persistence of such large current account deficits, which were intvifably financed